

संक्षिप्त

जर्जर आंगनवाड़ी से सुरक्षा को खतरा

तिरोडा : तहसील के काचेवानी स्थित आंगनवाड़ी क्रमांक-1 की जर्जर इमारत के कारण बच्चों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है. आंगनवाड़ी सेविका शालिनी आकाश असादी ने महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा पंचायत समिति को ज्ञापन सौंपकर भवन के पुनर्निर्माण अथवा वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है. ज्ञापन में बताया गया है कि आंगनवाड़ी भवन काफी पुराना हो चुका है, जहां 2 से 4 वर्ष आयु के छोटे बच्चे नियमित रूप से आते हैं.

रेलवे फाटक से वाहन चालक परेशान

गोंदिया : आमगांव तहसील में मुंबई-हावड़ा रेल मार्ग पर स्थित गोंदिया-आमगांव सड़क मार्ग पर किंग्डीपार कार रेलवे फाटक माल व यात्री वाहनों के लिए बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है. इस मार्ग पर रेलवे फाटक पर फलाईओवर की मांग लंबित है. इसके अलावा आमगांव-गोंदिया सड़क का चौड़ाईकरण और नव निर्माण किया गया. लेकिन नागरिकों द्वारा सवाल किया जा रहा है कि क्या नई सड़क का निर्माण तो किया गया, लेकिन रेलवे फलाईओवर का निर्माण कब किया जाएगा.

छात्रवृत्ति योजना के आवेदन आमंत्रित

गोंदिया : केंद्र सरकार की पीएम यशस्वी (प्रधानमंत्री यंग अचिह्नर्स छात्रवृत्ति अवार्ड पुरस्कार योजना फॉर वायब्रेट इंडिया) के तहत स्कूलों में शीर्ष स्तरीय शिक्षा योजना का कार्यान्वयन शुरू हो गया है, और पात्र छात्रों से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर आवेदन करने का आह्वान किया गया है. इस योजना के तहत, राज्य के शीर्ष विद्यालयों में पढ़ने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़े वर्ग (ईबीसी) और विमुक्त जाति और भटक्या जमाति (डीएनटी) श्रेणियों से संबंधित कक्षा 9वीं और 11वीं के पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है. इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 जून 2026 से शुरू हो गए हैं.

विद्यार्थियों के सामने आवास का संकट अर्जुनी मोरगांव का शासकीय छात्रावास बंद

नई इमारत के निर्माण में अभी देर

संवाददाता / अर्जुनी मोर सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभाग, महाराष्ट्र शासन के अंतर्गत संचालित भारतरत्न डा. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय लड़कों का छात्रावास, अर्जुनी मोरगांव को जर्जर व खतरनाक इमारत के कारण प्रशासन ने अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। वर्षों किराए के इमारत में संचालित हो रहा यह छात्रावास पूरी तरह जर्जर हो चुका था। विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने इमारत खाली कराने का निर्णय लिया है। शैक्षणिक सत्र



शुरू होने के बीच छात्रावास बंद होने से ग्रामीण क्षेत्र के सैकड़ों विद्यार्थियों के सामने रहने की गंभीर समस्या निर्माण हो गई है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों की पढ़ाई पर इसका सीधा असर पड़ रहा है और उनके भविष्य पर भी संकट मंडराने लगा है। बताया जा रहा है कि नई इमारत

पूरी तरह तैयार है, लेकिन उद्घाटन की औपचारिकता पूरी नहीं होने के कारण उसे शुरू नहीं किया जा सका है। इस स्थिति से सबसे अधिक परेशानी दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों से पढ़ाई के लिए आए विद्यार्थियों को हो रही है। निजी कमरा किराए पर लेकर रहना अधिकांश गरीब छात्रों की आर्थिक क्षमता से बाहर है। छात्रावास बंद होने के कारण कई विद्यार्थी नियमित कक्षाओं, प्रायोगिक परीक्षाओं और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों से वंचित हो रहे हैं। छात्रों के शिक्षा के अधिकार

किराए की इमारत में चल रहा था छात्रावास, अब वह भी बंद

जानकारी के अनुसार, छात्रावास जिस किराए के इमारत में संचालित हो रहा था, वह रहने योग्य नहीं बचा था। इसके चलते प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से वहां विद्यार्थियों का निवास बंद करा दिया। छात्रावास में रह रहे सभी छात्रों को अपना सामान लेकर बाहर जाना पड़ा। प्रभारी गृहपाल द्वारा विद्यार्थियों के आधिकारिक व्हाट्सएप समूह में भेजे गए संदेश के अनुसार, नई शासकीय छात्रावास इमारत का औपचारिक उद्घाटन होने तक विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

के साथ अन्याय है। उनका कहना है कि प्रशासनिक देरी का खामियाजा गरीब विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। विद्यार्थी संगठनों और पालकों ने प्रशासन से नए छात्रावास को तत्काल शुरू करने की मांग की है। उन्होंने

सड़कों पर कीचड़ फैला रहे ट्रैक्टर

संवाददाता / सालेकसा तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्रों की मुख्य सड़कों पर खेतों से आने-जाने वाले ट्रैक्टरों के पहियों से गिर रही मिट्टी और कीचड़ के कारण दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. सड़क पर हुई फिसलन से दोपहिया, चारपहिया वाहन चालकों और पैदल यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर संकट मंडरा रहा है. ऐसे में यदि कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, यह सवाल स्थानीय नागरिक कर रहे हैं.

बारिश के मौसम में ट्रैक्टरों के पहियों से चिपकी मिट्टी और कीचड़ मुख्य सड़कों पर फैल जाता है. इससे सड़क अत्यधिक फिसलन भरी हो जाती है और विशेषकर दोपहिया वाहन चालकों के संतुलन बिगड़ने का खतरा बना रहता है. रात के समय या तेज गति से आने वाले वाहन चालकों के लिए यह स्थिति और भी अधिक जोखिमपूर्ण हो जाती है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या नई नहीं है, बल्कि लंबे समय से बनी हुई है. संबंधित विभागों का



ध्यान कई बार इस ओर दिलाया गया, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है. इससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं. नागरिकों ने खेतों से मुख्य सड़क पर आने से पहले ट्रैक्टरों के पहिए पर लगी मिट्टी और कीचड़ साफ करने की मांग ट्रैक्टर चालकों से की है. साथ ही ग्राम पंचायत, सार्वजनिक लोकनिर्माण विभाग तथा यातायात विभाग से इस संबंध में सख्ती बरतते हुए लापरवाह वाहन चालकों पर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है. लोगों का कहना है कि किसी बड़े हादसे का इंतजार करने के बजाय प्रशासन को तत्काल सड़कों की सफाई कर प्रभावी व्यवस्था लागू करनी चाहिए, ताकि भविष्य में दुर्घटनाओं को रोका जा सके.

चंद्रपुर रेल मार्ग पर अंडरपास नहीं ओवरब्रिज बनाया जाए

आंदोलन कर रहे लोगों से मिले विधायक अग्रवाल अधिकारियों से कहा- दो दिन में सर्वे रिपोर्ट दें

संवाददाता / गोंदिया गोंदिया-चंद्रपुर रेल मार्ग पर स्थानीय भीमनगर रेलवे क्रासिंग को बंद करने के लिए बनाए जा रहे भूमिगत अंडर पास का विरोध कर वहां पर ओवरब्रिज बनाने की मांग को लेकर आंबेडकर वार्ड, सिंगलटोली, भीमनगर, कुंभारनगर, चंद्रशेखर वार्ड के नागरिक लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। कई दिनों से बेमियादी अनशन भी चल रहा है।

13 जुलाई को इस मामले पर विधायक विनोद अग्रवाल ने दखल देते हुए प्रशासन व रेल अधिकारियों की टीम के साथ मौके का जायजा लिया। विधायक अग्रवाल ने



अधिकारियों की संयुक्त टीम को दो दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। विधायक ने कहा जल्द ही एक उच्च स्तरीय बैठक लेकर सर्वे रिपोर्ट के आधार पर समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान नागरिकों ने कहा कि रेलवे आम नागरिकों की सुविधा देखे बिना मनमर्जी से काम कर रहा है।

आवाजाही बंद हो गई है। आवागमन भीमनगर रेलवे क्रासिंग से हो रहा है। अब यदि चंद्रपुर रेल लाइन पर अंडरपास का निर्माण होता है, तो ये हजारों लोगों पर अन्याय होगा। इस समय नगराध्यक्ष सचिन शेंडे, नगरसेवक सुनील भालेराव, आंदोलन कर रहे अमित भालेराव, नगरसेवक पंकज यादव, सुनील भरने, स्नेहा गडपायले, जिला प्रशासन की ओर से एसडीओ चंद्रभान खंडाईत, तहसीलदार शमशेर पठान, नप मुख्याधिकारी संदीप बोरकर, लोकनिर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता, रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर मल्लिकार्जुन राव उपस्थित थे।

150 वर्ष पुराने पेड़ को जेसीबी से उखाड़ा, कार्रवाई नहीं

संवाददाता / गोंदिया वनपरिक्षेत्र अंतर्गत गोरेगांव तहसील के मुरदोली बफर जोन हाईवे क्षेत्र के लगभग डेढ़ सौ वर्ष पुराने पेड़ को कुछ दिन पहले जेसीबी से किसी अज्ञात ने उखाड़ दिया था। बता दें कि वन्यजीव, वन विभाग व जिला प्रशासन की ओर से जिले को हरा बनाने के लिए लाखों पौधों का रोपण कर रहा है। लेकिन पर्यावरण संरक्षण के दावे असफल साबित हो रहे हैं।



नेशनल हाईवे गुजरता है। मुरदोली से लेकर भंडगा तक बफर जोन होने से विभाग ने इस मार्ग तक नेशनल हाईवे के चौड़ाईकरण को मंजूरी नहीं दी है। क्योंकि चौड़ाईकरण से हजारों पेड़ों की

कटाई होगी। 12 जुलाई को पेड़ काटने की शिकायत मुरदोली ग्रामसभा, सामूहिक वन अधिकार संवर्धन व व्यवस्थापन समिति ने कार्रवाई की मांग करते हुए जिलाधिकारी से की है।

स्कूल में बैठने बेंच नहीं, ग्राम पंचायत कार्यालय में धरने पर बैठे विद्यार्थी

रावणवाड़ी के जिप स्कूल में पढ़ते हैं 120 छात्र, चार माह से बेंचों की मांग कर रहे

संवाददाता / गोंदिया जिला परिषद स्कूलों में विद्यार्थियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसके लिए हर वर्ष लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। लेकिन खर्च करने के बावजूद विद्यार्थियों को सुविधाओं के लिए तरसना पड़ रहा है। इसी तरह का हाल गोंदिया तहसील के रावणवाड़ी स्थित जिला परिषद स्कूल में देखने को मिल रहा है। यहां विद्यार्थियों को बैठने बेंच नहीं हैं। जिससे नाराज अभिभावकों, शाला व्यवस्थापन समितियों के पदाधिकारियों विद्यार्थियों ने 13 जुलाई को ग्राम पंचायत कार्यालय के



समक्ष धरना आंदोलन कर प्रशासन का ध्यानकर्षण कराया। बता दें कि रावणवाड़ी स्थित 110 वर्ष पुराने जिला परिषद स्कूल में पहली से सातवीं तक कक्षाएं हैं। जहां लगभग 120 विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन कक्षाओं में बैठने के

लिए बेंच ही नहीं हैं। शाला व्यवस्थापन समिति 4 माह से विद्यार्थियों के बैठने के लिए बेंच की मांग कर रही है। बावजूद शिक्षा विभाग, ग्राम पंचायत इस समस्या की ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही है।

गोंदिया में भारतीय विधवा महिला फाउंडेशन की बैठक संपन्न

विधवा एवं एकल महिलाओं के लिए ५००० मासिक पेंशन की मांग

संवाददाता / तिरोडा भारतीय विधवा महिला फाउंडेशन के तत्वावधान में शहर के टीवी टोली क्षेत्र में विधवा एवं एकल महिलाओं की समस्याओं, अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में विधवा एवं एकल महिलाओं ने भाग लेकर अपने जीवन के संघर्ष, आर्थिक कठिनाइयों और सामाजिक उपेक्षा से जुड़े अनुभव साझा किए। महिलाओं की पीड़ा सुनकर उपस्थित पदाधिकारी भावुक हो

गए। बैठक में संगठन की राष्ट्रीय सचिव एवं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी रूपाली यादवराव ऊके मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थीं। उनके साथ प्रदेश सह सचिव वनिता ठाकरे ने भी सहभागिता की। कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय स्तर पर पद्मा ऊके एवं कुंदा अरविंद चंद्रकार के संयुक्त प्रयासों से किया गया। बैठक के दौरान महिलाओं ने पति की मृत्यु के बाद आने वाली आर्थिक परेशानियों, सामाजिक असुरक्षा और उपेक्षा से जुड़े अपने



अनुभव साझा किए। कई महिलाओं की मार्मिक आपबीती सुनकर कार्यक्रम का माहौल भावुक हो गया। राष्ट्रीय सचिव रूपाली यादवराव ऊके भी

महिलाओं की पीड़ा सुनकर भावुक हो उठीं। प्रदेश सह सचिव वनिता ठाकरे ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन प्रत्येक विधवा एवं एकल

महिला के सम्मान, अधिकार और आत्मनिर्भरता के लिए निरंतर कार्य करेगा। उन्होंने महिलाओं से स्वयं को कमजोर या अकेला न समझने का आह्वान करते हुए कहा कि भारतीय विधवा महिला फाउंडेशन हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा रहेगा। बैठक में संगठन की ओर से प्रमुख मांग उठाई गई कि विधवा एवं एकल महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीवनयापन के लिए सरकार द्वारा कम से कम 5000 प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाए। वक्ताओं ने कहा कि

आर्थिक सुरक्षा प्रत्येक महिला का अधिकार है और इस मांग को शासन-प्रशासन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों कुंदा अरविंद चंद्रकार एवं पद्मा ऊके ने सभी अतिथियों तथा उपस्थित महिलाओं का आभार व्यक्त किया। साथ ही महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई को और अधिक मजबूती से आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। बैठक में महिलाओं के हितों की रक्षा तथा उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए संगठन को और मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया।



संवाददाता / तिरोडा प्रहार जनशक्ति पार्टी द्वारा विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर दिए गए ज्ञापन और प्रस्तावित आंदोलन की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया। जिलाधिकारी मंदार पतकी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों

की ओवरलॉड राख एवं कोयला परिवहन से फैल रहे प्रदूषण, देवरी तहसील में प्रस्तावित एथेनॉल परियोजना के लिए किसानों के सिंचाई जल को रोके जाने की आशंका, किसानों को धान बोनस, समर्थन मूल्य तथा लंबित भुगतान दिलाने का मुद्दा भी उठाया। वन विभाग से संबंधित

महेंद्र भांडारकर ने उठाए किसानों, महिलाओं, बिजली, प्रदूषण व वन्यजीव मुआवजे समेत आठ प्रमुख मुद्दे

विषयों पर भी चर्चा करते हुए वन्यजीवों के हमलों में घायल व्यक्तियों एवं

के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। बैठक में प्रहार के जिलाध्यक्ष महेंद्र भांडारकर तथा जिलासचिव महेंद्र नंदगवली ने जिले की प्रमुख समस्याओं को विस्तार से प्रशासन के समक्ष रखा। उन्होंने बताया कि पात्र महिलाओं को लाइकी बहिण योजना का लाभ समय पर नहीं मिल रहा है। किसानों को कृषि पंपों के लिए 24 घंटे विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है, जबकि घरेलू बिजली की बार-बार कटौती से आम नागरिक भी परेशान हैं। इसके अलावा सोलर कृषि कनेक्शन एवं समेत आ रही तकनीकी खामियों, स्मार्ट मीटर संबंधी शिकायतों तथा बीडी श्रमिकों की पेंशन बढ़ाने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। शिष्टमंडल ने अडानी कंपनी

मृत पशुधन के लिए मिलने वाली अनुदान राशि बढ़ाने तथा एक माह के भीतर मुआवजा प्रदान करने की मांग की गई। प्रहार संगठन ने इन सभी मांगों के निराकरण के लिए 14 जुलाई से आंदोलन की चेतावनी दी थी। आंदोलन से पहले ही जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के प्रमुख अधिकारियों की बैठक बुलाकर सभी मामलों की समीक्षा की और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में प्रहार के जिलाध्यक्ष महेंद्र भांडारकर, जिलासचिव महेंद्र नंदगवली, जिलाध्यक्ष पिंटू बावनकर तथा संगठन के पदाधिकारी बिसेन सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

संपादकीय

टकराव और बढ़ेंगा

राष्ट्रपति ट्रंप ने ३६ घंटे में पांच बार धमकियां दी हैं कि यदि ईरान ने उनकी हत्या कराने की कोशिश की, तो अमरीका उसे तबाह कर देगा, मिट्टी मलबा कर देगा। इसके लिए उन्होंने अमरीकी सेना को आदेश भी दे दिए हैं। पेंटागन एक लंबे साल तक ईरान पर हमले करने और बमबारी करने की तैयारी में जुट गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी खुलासा किया है कि १००० मिसाइल 'लॉक' और 'लैंडेड' कर दी गई हैं। अर्थात उनके निशाने तय कर दिए गए हैं। यदि राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की गई, तो ईरान पर मिसाइलों और ताकतवर बमों की बारिश कर दी जाएगी। ईरान को लगभग नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। दूसरी ओर, ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने सार्वजनिक रूप से कसम खाई है कि उनके पिता और ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अली खामेनेई और जंग में मारे गए लोगों का इंतकाम जरूर लिया जाएगा। यह ईरानी अवाक की मांग और भावनाएं भी हैं। मुज्तबा ने ट्रंप और नेतनयाहू को 'दुश्मन' करार दिया है। सुप्रीम लीडर के फरमान से साफ है कि दोनों की हत्या की जाए। सुप्रीम लीडर ने, अंततः, यहां तक कहा, 'हम रहें या न रहें, लेकिन बदला हर हाल में लिया जाएगा।' ट्रंप और मुज्तबा के बयान बेहद भयानक और खौफनाक हैं। यदि राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की जाती है अथवा ईरान की साजिश वाली रणनीति कामयाब हो जाती है, तो अमरीका और ईरान ही नहीं, दुनिया के एक बड़े भूभाग में प्रलय मच जाएगी। विश्लेषकों के आकलन हैं कि ईरान युद्ध से वैश्विक अर्थव्यवस्था २.२ ट्रिलियन डॉलर का नुकसान झेल चुकी है। ऊर्जा, गैस, खाद्य, मशीनरी, उर्वरक की आपूर्ति बाधित है, तो विश्व में ऐसे संकटों का भी तनाव बना रहेगा। अभी तक देशों ने अपने रिजर्व तेल भंडारों का इस्तेमाल किया है और युद्ध समाप्त होने की प्रार्थनाएं कर रहे हैं। यदि देशों के तेल भंडार भी खत्म होने लगेंगे, तो कच्चे तेल की कीमतें कौनसे आसमान तक जाएंगी, उनका अनुमान अभी संभव नहीं है।

भारतीय अर्थशास्त्री मान रहे हैं कि यदि युद्ध ३-४ सप्ताह और खिंच गया, तो कच्चा तेल १२०-१४० डॉलर प्रति बैरल तक उछल सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि भारत को भी आर्थिक-ऊर्जा संबंधी चुनौतियां झेलनी पड़ेंगी। अभी तक गोदाम भरे थे, लिहाजा कोई चिंता नहीं थी, लेकिन गोदाम खाली होने के बाद कुल नुकसान १५० लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। यह भारत की कुल जीडीपी से दोगुना से भी अधिक है। दरअसल बुनियादी सवाल यह है कि क्या ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप को मारने का रोडमैप तक तैयार कर लिया है अथवा इजरायल की खुफिया एजेंसी 'मोसाद' की सपट के आधार पर ही हत्या की धमकियां दी जा रही हैं? किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष की जिंदगी पर मौत के भयावह साप मंडराते ही रहते हैं लेकिन ट्रंप पर राष्ट्राध्यक्ष बनने से पहले और बाद में जानलेवा हमले किए गए हैं। यहां तक खबरें हैं कि ईरान ने अमरीका में ही अपने 'स्लीपर सेल्स' सक्रिय कर दिए हैं। मेक्सिको के इन्स तस्करो से भी बातचीत की खबरें सामने आई हैं, क्योंकि वे भी राष्ट्रपति ट्रंप के धुर विरोधी हैं और उनके गिरोह बेहद ताकतवर और हथियार माने जाते हैं। बहरहाल हम ऐसी खबरों की पुष्टि नहीं कर सकते। फिर भी सवाल है कि क्या ऐसी साजिशें भी अमरीकी राष्ट्रपति की हत्या कर सकती हैं? अमरीका ने अब्राहम लिंकन, जेम्स ए मैरीफील्ड, विलियम मैकिनल, जॉन एफ कैनेडी सरीखे चार राष्ट्रपतियों के हत्याकांड देखे और झेलें हैं, लिहाजा ट्रंप की सुरक्षा में अतिरिक्त, कड़े, बहु लेयर बंदोबस्त किए जा रहे हैं। क्वाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप ने खुफिया एजेंसियों की अपातकालीन बैठक बुलाई थी।

स्वास्थ्य सेवाओं के लंबित प्रस्ताव तुरंत सुलझाएं

गढ़चिरौली : राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के निदेशक तथा स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त संजय काटकर ने कहा कि गढ़चिरौली जिले में स्वास्थ्य विभाग के सरकारी स्तर पर लंबित पड़े प्रस्ताव तुरंत सुलझाए जाएं। आयुक्त काटकर ने शनिवार, ११ जुलाई को जिले का दौरा करके स्वास्थ्य सेवा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत विभिन्न योजनाओं, मानव संसाधन, सुविधाओं तथा दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था का अवलोकन किया।

इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय और जिला परिषद में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकों की, वहीं देसाईगंज (वडसा) तहसील के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुरुड का दौरा करके स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत की। यहां चल रहे 'सर्वसमावेशी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा' प्रशिक्षण वर्ग का निरीक्षण किया। प्रशिक्षणार्थियों से सीधे बातचीत करके उन्होंने प्रशिक्षण की गुणवत्ता, सेवा वितरण की स्थिति और ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था में आने वाली चुनौतियों की जानकारी लेकर कहा कि गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण से



नए स्वास्थ्य केंद्र के प्रस्तावों को मंजूरी दें

जिलाधिकारी अविश्यांत पंडा ने बैठक में जिले में क्षय और कुष्ठरोग उन्मूलन के लिए साल में दो बार विशेष जांच अभियान चलाने के साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों के मरीजों को तुरंत चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त १०८ एम्बुलेंस उपलब्ध कराने और बाहरी स्रोतों से चालकों की नियुक्ति करने का अनुरोध किया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे ने जिले में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उपकेंद्रों के प्रस्तावों को तुरंत मंजूरी देने का अनुरोध किया और आवश्यक पदों की भर्ती आदेश जारी करने की मांग की।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सक्षम बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने आशा स्वयंसेविकाओं के काम की विशेष रूप से सराहना की। इस दौरान नागपुर मंडल के उपसंचालक डॉ. शशिकांत शंबरकर, एचएफडब्ल्यूटीसी के प्राचार्य डॉ. श्रीराम गोगुलवार, जिला स्वास्थ्य

अधिकारी डॉ. प्रताप शिंदे, जिला शल्य चिकित्सक डॉ. वर्षा लहाड़े, अतिरिक्त जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संतोष कोटुले, जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. माधव शिंदे, चिकित्सा अधिकारी डॉ. सचिन हेमके, तहसील स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आनंद ठिकरे उपस्थित थे।

वर्धा : वन्यजीवों को प्राकृतिक चारा उपलब्ध कराने, भोजन की तलाश में जंगल से बाहर भटकने की समस्या कम करने तथा वन क्षेत्रों के घासयुक्त भूभाग के संरक्षण के उद्देश्य से समुद्रपुर तहसील के खुर्सापार टाइगर सफारी परियोजना के अंतर्गत गिरइ बीट के कक्ष क्रमांक 315 स्थित आरक्षित वन में श्रमदान के माध्यम से 10 हेक्टेयर क्षेत्र में घास के चारागाह विकास का विशेष अभियान चलाया गया. इस दौरान विभिन्न प्रजातियों की घास के बीजों बोए गए.

यह अभियान उपवन संरक्षक हरविंदर सिंह के मार्गदर्शन तथा सहायक उपवन संरक्षक हरीश सरोदे की उपस्थिति में

रैगिंग से फिर गरमाया एमएनएलयू कैंपस

नागपुर : महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एमएनएलयू) में एक रैगिंग का मामला सामने आया है. यहां 'इंट्रोडक्शन' के नाम पर कुछ वरिष्ठ छात्रों द्वारा रैगिंग किए जाने की शिकायत एक छात्र ने दर्ज कराई थी. शिकायत पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन की रिपोर्ट के बाद बूटीबोरी पुलिस ने चार छात्रों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया. हालांकि, बाद में पुलिस ने इन छात्रों को समझाइश देकर छोड़ दिया. इस कार्रवाई के विरोध में विभिन्न छात्र संगठनों ने शनिवार रात

विविध परिसर में आंदोलन किया. शनिवार को रैगिंग से पीड़ित छात्र की शिकायत पर एमएनएलयू प्रशासन ने बूटीबोरी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने ४ छात्रों को गिरफ्तार किया. न्यायालय द्वारा उन्हें जमाना पर छोड़ दिया गया. इसके बाद छात्र संगठनों ने परिसर में आंदोलन किया. छात्रों का कहना है कि उन्होंने रैगिंग नहीं की, केवल नाम पूछा था. संगठन ने आरोप लगाया कि संबंधित छात्र महाराष्ट्रीयन होने के कारण प्रशासन ने प्रांतवाद की

मानसिकता से यह कार्रवाई की है. आंदोलनकारी छात्रों के अनुसार, रैगिंग की कथित घटना केवल एक सामान्य परिचय जैसी थी, जिसमें सीधे पुलिस बुलाने जैसा कुछ गंभीर नहीं था. नियमानुसार रैगिंग की शिकायत पहले विवि की एटी-रैगिंग समिति के पास भेजनी चाहिए थी. प्रशासन में इस समय क्षेत्रवाद, पक्षपात और जातिवाद हावी है. महाराष्ट्र के बाहर के अधिकारी व प्राध्यापक जानबूझकर महाराष्ट्रीयन छात्रों पर अन्याय कर रहे हैं.

जमीन का मालिकाना हक मिलने की उम्मीद जागी



वर्धा : हिंगणघाट फ़ैल के नागरिकों के मालिकाना हक के समाधान की दिशा में अहम कदम, राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक है. इस बैठक के बाद जमीन का मालिकाना हक मिलने की उम्मीद नागरिकों में जागी है.

पुलगांव स्थित हिंगणघाट फ़ैल में वर्षों से लंबित नागरिकों के मालिकाना हक और मकानों के नियमितकरण के मुद्दे पर विधायकवन, मुंबई में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में विधायक राजेश बकाने ने नागरिकों की समस्याओं को विस्तार से रखते हुए इस मुद्दे का शीघ्र समाधान करने की मांग की. बैठक में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, विधायक बकाने, एड. दिशेश शर्मा, अशोक पनपलिया तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. वहीं, वर्धा की जिलाधिकारी वान्मथी सी. ऑनलाइन बैठक में शामिल हुई.

राजस्व मंत्री की उपस्थिति में मुंबई में बैठक

हिंगणघाट फ़ैल के सैकड़ों परिवार वर्षों से मालिकाना हक के अभाव में विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं. स्वामित्व संबंधी दस्तावेज नहीं होने के कारण उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ, बैंक ऋण, मकान निर्माण तथा संपत्ति हस्तांतरण जैसी कई सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है. बकाने एवं प्रतिनिधि मंडल ने इस मामले में सकारात्मक निर्णय लेकर नागरिकों को न्याय दिलाने की मांग की. बैठक में विधायक बकाने ने संबंधित राजस्व अभिलेख, उपलब्ध दस्तावेज और कानूनी पहलुओं की जानकारी दी. इसके बाद राजस्व मंत्री बावनकुले ने मामले की गंभीरता को देखते हुए वर्धा के जिलाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई तत्काल शुरू करने तथा नियमानुसार मालिकाना हक प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए.

1.29 करोड़ का 6001 विपंटल धान डकार गया मिल मालिक

अपराध । और धान देने पर ही राशि मिलने की बात कहकर धमकाया : सुनील रामनानी, मतीन अहमद कुरैशी के खिलाफ मामला दर्ज

ब्रह्मपुरी : तहसील का धान व्यापार से जुड़ा करोड़ों रु. का कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. धान कारोबारियों को विश्वास में लेकर धान खरीदने, भुगतान न करने व रकम मांगने पर धमकी देने के आरोप में एक दलाल और राइस मिल संचालक के खिलाफ ब्रह्मपुरी पुलिस थाने में बीएनएस २०२३ की धारा ३१६(२), ३५१(२) एवं ३५(१) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, अरहर नवरगांव (तहसील ब्रह्मपुरी) निवासी नंदकिशोर वैद्य पिछले कई वर्षों से खेती के साथ धान खरीद-बिक्री का व्यवसाय कर रहे हैं. उनकी पत्नी के नाम से संचालित साईं कृषि केंद्र के माध्यम से भी धान का व्यापार किया जाता है. इसी व्यवसाय के दौरान उनकी पहचान देसाईगंज निवासी सुनील रामनानी से हुई थी.

जो काफी समय से धान दलाल के रूप में



कार्य कर रहे थे. पूर्व में उनके माध्यम से हुए कई लेन-देन समय पर पूरे होने से शिकायतकर्ता को उन पर विश्वास हो गया था. शिकायत के अनुसार, वर्ष २०२५ में रामनानी ने भंडारा जिले के शिंगोरी स्थित केएमसी ग्रेन मिलिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट एलएलपी में ब्रह्मपुरी की तुलना में अधिक भाव मिलने का भरोसा दिलाकर धान भेजने की

सलाह दी.

प्रारंभ में दो माह बाद भुगतान होने की शर्त पर शिकायतकर्ता ने संदेह जताया. लेकिन रामनानी द्वारा भुगतान की पूरी जिम्मेदारी लेने का आश्वासन देने पर उन्होंने १० जून २०२५ से ५ अगस्त २०२५ के बीच २२ ट्रकों में कुल ६००१.०५ विपंटल धान, जिसकी कीमत १ करोड़ २९ लाख १० हजार ३२ रु. बताई गई है, संबंधित कंपनी को भेज दिया. शिकायत के आधार पर ब्रह्मपुरी पुलिस सुनील रामनानी तथा केएमसी ग्रेन मिलिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट एलएलपी के संचालक मतीन अहमद कुरैशी के खिलाफ मामला दर्ज करके प्रकरण की विस्तृत जांच कर रही है.

एक नहीं ८० व्यापारी हुए धोखाधड़ी का शिकार !

इसी बीच व्हाटसएप पर चल रहे एक रिकवरी ग्रुप में सुनील रामनानी के नाम पर

टालमटोल करके परिणाम भुगतने की धमकी दी

निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी भुगतान नहीं मिलने पर शिकायतकर्ता ने कई बार संपर्क किया. आरोप है कि शुरुआत में आठ दिन रुकिए और बैंक का कर्ज शुरू है जैसे कारण बताकर टालमटोल किया गया. बाद में देसाईगंज कार्यालय पहुंचकर भुगतान की मांग करने पर उन्हें कथित रूप से गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई. शिकायत में यह भी कहा गया है कि बाद में शिकायतकर्ता एवं अन्य व्यापारियों ने केएमसी कंपनी के अधिकारियों से मुलाकात की. इस दौरान कंपनी के संचालक मतीन अहमद गनी अहमद कुरैशी ने कुछ समय इंतजार करने का आश्वासन दिया, लेकिन इसके बाद भी भुगतान नहीं किया गया. पुनः पूछताछ करने पर कथित रूप से कहा गया कि पहले और धान दीजिए, मिल चलती रही तो पैस मिलेंगे, अन्यथा जो करना है कर लीजिए.

जमीन हस्तांतरण से संबंधित दस्तावेज वायरल होने के बाद शिकायतकर्ता का संदेह और गहरा गया. इस संबंध में पूछताछ करने पर भी संतोषजनक जवाब नहीं मिलने का आरोप लगाया गया है. शिकायत के अनुसार, ८ अप्रैल २०२६ को केएमसी कंपनी पहुंचने पर पता चला कि उनके जैसे लगभग ८० व्यापारी भी कथित धोखाधड़ी

का शिकार हुए हैं. मामले में शिकायतकर्ता नंदकिशोर वैद्य के अलावा दो अन्य व्यापारियों को भी भारी आर्थिक नुकसान होने का दावा किया गया है. इनमें विनोद कावले के लगभग ७५ लाख ७० हजार ८१६ रु. तथा रामदास हरिभाऊ जिभकाटे के करीब १० लाख ४४ हजार ५२१ रु. का भुगतान अब तक लंबित होने की बात शिकायत में कही गई है.

देसाईगंज में दूषित जलापूर्ति; लोगों का स्वास्थ्य खतरे में

नगर परिषद प्रशासन की लापरवाही पर उठे गंभीर सवाल

देसाईगंज : नगर परिषद प्रशासन की लापरवाही का एक और चैंकाने वाला मामला सामने आया है. सोमवार, १३ जुलाई की सुबह ब्रह्मपुरी मार्ग स्थित गांधी वाई निवासी सुनील वामन मेश्राम के घर में पीने के पानी की पाइपलाइन से केकड़ा निकलने की घटना ने शहरवासियों की चिंता बढ़ा दी है. साथ ही नगर परिषद के जलापूर्ति विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल किए जा रहे हैं.

देसाईगंज शहर में जगह-जगह जलापूर्ति योजना की पाइपलाइन में लीकेज होने से गंदा और दूषित पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है. कई बार नलों से मिट्टी, कीड़े-मकोड़े और अन्य गंदगी निकलने की शिकायतें सामने आ चुकी हैं. अब पाइपलाइन से केकड़ा निकलने से नागरिकों में भारी नाराजगी देखी जा रही है. लोगों का कहना है कि जब पाइपलाइन में केकड़ा पहुंच सकता है, तो दूषित जलापूर्ति से बीमारियां फैलना तय है. दूषित पानी पीने से शहर में हर घर के लोग बीमार पड़ रहे हैं. इसके बावजूद नगर परिषद के जिम्मेदार मुख्याधिकारी और पदाधिकारी

समस्या का स्थायी समाधान करने के बजाय आंखें बंद करके बैठे हैं. नागरिकों की मांग है कि दोषी अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए. शहर की पूरी जलापूर्ति व्यवस्था की जांच कराई जाए, सभी लीकेज पाइपलाइन बदल दी जाएं और सभी प्रभागों की जनता को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाए.

एक घर में जलापूर्ति के दौरान निकला केकड़ा

आंदोलन के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ कुछ माह पहले विधायक रामदास मसरराम के मार्गदर्शन में कांग्रेस पार्टी ने गंदे पानी की सफाई के विरोध में मोर्चा निकालकर नगर परिषद का घेराव किया था. उस समय अधिकारियों ने सुधार के बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन आज भी परिस्थितियां वैसी की वैसी बनी हुई हैं. शहर के कई बाड़ों में पाइपलाइन में रिसाव होने से घरों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच रहा है. जबकि वहीं दूसरी ओर नगर परिषद टैक्स वसूली में पूरी सख्ती बरत रही है.

वन्यजीवों के लिए प्राकृतिक चारे की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 73 किलो घास प्रजातियों के बीजों की बुआई



आयोजित किया गया. कार्यक्रम में वन विभाग के कर्मचारी, वन मजदूर, रोपण चौकीदार, आरआरटी के सदस्य, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने श्रमदान कर सक्रिय भागीदारी निभाई. गिरइ

ग्राम पंचायत के प्रशासक राजू नौकरकर, मोहगांव ग्राम पंचायत के प्रशासक विलास नवघरे, शिवणफल संयुक्त वन प्रबंधन (जेएफएम) समिति के अध्यक्ष गजानन गारघाटे, समुद्रपुर वनपरिक्षेत्र अधिकारी स्वप्निल ढोणे,

गिरइ के क्षेत्र सहायक गणेश राऊत, कोरा क्षेत्र सहायक विकास चौधरी, क्षेत्र सहायक राजेंद्र धनवीज, मंगरुल क्षेत्र सहायक सुनील देहनकर, गिरइ के वनरक्षक पी. डी. बेले तथा खुर्सापार जेएफएम समिति के अध्यक्ष

सदाशिव राऊत सहित अन्य अधिकारी एवं ग्रामीण उपस्थित थे. अभियान के दौरान घोन्घाड, मोती तुरा, बेर, बड़ी डोंगरी, छोटी डोंगरी, मोशन तथा रान शेवरा जैसी घास की प्रजातियों के कुल 73 किलोग्राम बीजों की बुआई की गई. वन विभाग के अनुसार इस पहल से वन क्षेत्र में प्राकृतिक घास के चारागाह विकसित होंगे, जिससे शाकाहारी वन्यजीवों के लिए चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी और वन पारिस्थितिकी व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी. सहायक उपवन संरक्षक हरीश सरोदे ने श्रमदान में सहयोग करने वाले सभी का आभार माना.

18 गांवों की स्वास्थ्य व्यवस्था एक डॉक्टर के भरोसे

ग्राम चिरोली प्राथमिक केंद्र की स्वास्थ्य सेवा चरमराई, रिक्त पद भरने की मांग

संवाददाता । मूल

ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को समय पर और बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की. लेकिन मूल तहसील के ग्राम चिरोली स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति इन दिनों बेहद चिंताजनक बनी हुई है. इस स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत १८ गांव आते हैं और इन सभी गांवों की स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी फिलहाल केवल एक ही चिकित्सा अधिकारी के कंधों पर है. स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के कई पद लंबे समय से रिक्त हैं. जिससे मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है. स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में ग्रामीणों को काफी



परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

चिरोली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्यक्षेत्र में चिरोली सहित जानाला, फुलझरी, आगडी, कांतापेट, टोलेवाही, केळझर, खालवसेपठ, सुशीदाबागांव,

दाबागांव मक्ता, नलेश्वर, भगवानपुर समेत कुल १८ गांव शामिल हैं. इन दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिदिन सैकड़ों मरीज उपचार के लिए यहां आते हैं. स्वास्थ्य केंद्र में दो चिकित्सा अधिकारियों के पद स्वीकृत हैं.

दवाओं की कमी, बाहर से खरीदने को मजबूर

चिरोली स्वास्थ्य केंद्र में केवल डॉक्टरों की ही नहीं, बल्कि आवश्यक दवाओं की भी कमी है. नागरिकों का आरोप है कि पर्याप्त दवा उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीजों को बाहर से दवाएं खरीदने की सलाह दी जा रही है. इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है. वर्तमान में बारिश के मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और संक्रामक बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ रही है. ऐसे समय में सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त दवाएं उपलब्ध नहीं होने से मरीजों को निजी मेडिकल दुकानों से महंगी दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं. ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से दवाओं की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा स्वास्थ्य केंद्र में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है.

लेकिन वर्तमान में केवल एक ही डॉक्टर कार्यरत है. बढ़ती मरीजों की संख्या और चिकित्सकों की कमी के कारण एकमात्र डॉक्टर पर अत्यधिक कार्यभार पड़ रहा है. इससे मरीजों को समय पर और समुचित उपचार मिलना मुश्किल हो रहा है. स्थिति

यह है कि कई मरीजों को इलाज के लिए पड़ोसी पोंभूर्णा तहसील के उपजिला चिकित्सकों की कमी के कारण एकमात्र डॉक्टर पर अत्यधिक कार्यभार पड़ रहा है. ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्ति कर स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ करने की मांग की है.

आंगनवाड़ी कर्मी और आशाओं का मोर्चा

कोरोना भत्ता के लिये कर्मी हुए आक्रामक

कर्मियों ने चार माह से नहीं मिला मानधन

आंदोलनकर्ताओं ने कहां कि, पहले ही कोरोना भत्ता नहीं मिलने के कारण आंगनवाड़ी कर्मी और आशा वर्कर को कोरोना भत्ता पाने के लिये संघर्ष करना पड़ रहा है. ऐसे में पिछले चार माह से संबंधित कर्मचारियों को मानधन नहीं दिया गया है. एक तरफ आंगनवाड़ी महिलाओं को पेंशन दिया जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय नुसार आंगनवाड़ी महिलाओं को ग्रेच्युटी लागू किया जाएगा ऐसा लिखित आश्वासन तीन वर्ष पहले राज्य सरकार ने दिया था. लेकिन तीन वर्षों की कालावधि बीत जाने के बाद भी इसपर अमल नहीं किया गया. जिससे सरकार की निति के प्रति आंगनवाड़ी कर्मियों में तीव्र नाराजगी व्याप्त है.

मारकवार, अरुण भेलके, किशोर जामदार, छाया कागदेलवर, अरुण लाटकर, विठाबाई भट्ट, सुनंदाबावणे ने किया. आंदोलन में गुलशन शेख, राजश्री खोब्रागडे, माया शेडमाके, ललिता केदार, उज्जला उंदीरवाडे, सुमन तोकलवार, रंजना चौकुंडे, भागीरथा दूधबावरे, रजनी चलकलवार, सिंधू मडावी, भारती रामटेके, सरिता आत्राम, छाया कागदेलवार, विश्रांती डोनालकर, कौशल्या गौरकार समेत बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कर्मी और आशा वर्कर उपस्थित हुए थे.

कांग्रेस ने किया भजन आंदोलन

संवाददाता । गड़चिरोली अयोध्या के राम मंदिर में कथित भ्रष्टाचार के विरोध में कांग्रेस ने गुरुवार 9 जुलाई को गड़चिरोली शहर के फुटका देऊल परिसर में स्थित हनुमान तथा श्रीराम मंदिर में ‘रघुपति राघव राजा राम’ भजन गाकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष एड. विश्वजीत कोवासे ने राम मंदिर की दान राशि तथा आभूषणों में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले के 88 आरोपी भाजपा समर्थक हैं. तथा उन्होंने लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई है. कोवासे ने कहा

कि अब तक भवन, सड़क तथा पुल निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की बातें सामने आती थीं, लेकिन अब मंदिर की दानपेटी की राशि तथा आभूषणों तक में कथित गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं. इस आंदोलन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एड. राम मेश्राम, प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज गुड्डेवार, शहर अध्यक्ष तथा पार्षद सतीश विधाते, अनुसूचित जाति सेल के जिलाध्यक्ष रजनीकांत मोटघरे, युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नितेश राठोड, नंदू वायलकर, पार्षद पराग पोरेड्डीवार, रमेश चौधरी, मीनल चिमूरकर, जितेंद्र मुनघाटे, प्रभाकर वासेकर, मनोज ढोरे, विजय लाड, विनोद लेनगुरे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे.

श्रीराम मंदिर में हुए चंदा चोरी के विरोध में कांग्रेस का सत्याग्रह

संवाददाता । वर्धा अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर की दान राशि में कथित अनियमितता एवं गबन के आरोपों को लेकर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर वर्धा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सोमवार को सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किया गया. जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनील कोल्हे, नगराध्यक्ष सुधीर पांगुल, डॉ. अभ्युदय मेघे, बाळकृष्ण माऊस्कर, राजेश शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस



सत्याग्रह आंदोलन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भजन-कीर्तन के माध्यम से विरोध दर्ज कराया और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग

की. इस सत्याग्रह की शुरुआत शहर के केसरीमल कन्या स्कूल स्थित काळा मारुति मंदिर में

फिर चारपाई पर मरीज को ले जाने की नौबत



प्त जानकारी के अनुसार, लाहेरी ग्रांप अंतर्गत आनेवाले

बंगाड़ी गांव निवासी संतोष जेठ्ठी (29) नामक व्यक्ति को मृत्युमार्ग बंद

लाहेरी परिसर में सामने आया मामला

होने के कारण पीड़ा हो रही थी. गंभीर संसर्ग होने के कारण उसकी हालत चिंताजनक हो रही थी. जिससे उसे तत्काल अस्पताल में पहुंचाना जरूरी हो गया था.

लेकिन रात के समय नदी में पानी और गांव तक पहुंचाने के लिये किसी भी तरह की वाहन सुविधा नहीं होने के कारण ग्रामीणों के सामने प्रश्न निर्माण हो

गया. आखिरकार ग्रामीणों ने संतोष को चारपाई पर रख नदी तक ले गये. इसके बाद जान जौखिम में डालकर टीन के नाव से नदी पार की गई. नदी पार करने के बाद दोबारा चारपाई से सफर शुरू किया गया.

इस मामले की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल एम्बुलस गुंडेनूर नाले तक

भिजवाया. वहां से मरीज को अस्पताल में लाया गया. डा. मिनल, गजेंद्र इंधये और संदीप गोटा ने मरीज की हालत को देख उसे भामरागड के ग्रामीण अस्पताल में रवाना किया. बंगाड़ी यह गांव लाहेरी से 7 किमी दूरी पर है. इस परिसर में स्वास्थ्य, सड़क और यातायात सुविधा का अभाव होने के कारण नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

पुलिस पर किया जानलेवा हमला

तीन पुलिसकर्मी घायल , 60 लोगों पर किया मामला दर्ज



पुलगांव शराबबंदी पथक के सहायक पुलिस निरीक्षक मल्हारी तालीकोटे, सावंगी थाने के उपनिरीक्षक मधुकर सामलवार, हिंगनघाट थाने के पुलिसकर्मी

करने पहुंचे थे. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बस स्टैंड क्षेत्र से अवैध देसी शराब का परिवहन करते हुए अंजित और उसकी पत्नी को दोपहिया वाहन सहित पकड़ लिया. पंचनामा की कार्रवाई चल रही थी, तभी अंजित की पत्नी ने मोबाइल फोन से अन्य लोगों को बुला लिया.

कुछ ही देर में 30 से 40 महिला-पुरुष मौके पर पहुंच गए और पुलिस के साथ अभद्रता करते हुए माहौल तनावपूर्ण बना दिया. इसी दौरान अंजित और उसकी

पत्नी पुलिस की गिरफ्त से भाग निकले. सूचना मिलने पर पुलगांव थाना प्रभारी ढाकणे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. बाद में पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की. इसी दौरान पारधी बस्ती में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस पर लाठियों, धारदार हथियारों तथा पत्थरों से हमला कर दिया. हमले में सहायक पुलिस निरीक्षक मल्हारी तालीकोटे, उपनिरीक्षक मधुकर सामलवार और पुलिसकर्मी सोनी नगराले घायल हो गए.

बैटरी चोर को किया गिरफ्तार

संवाददाता / हिंगनघाट हिंगनघाट पुलिस ने ट्रैक्टर बैटरी चोरी के मामले का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की तीन ट्रैक्टर बैटरियां तथा एक बिना नंबर की दोपहिया जप्त की हैं. बरामद माल की कुल कीमत 71 हजार रुपये बताई गई है. पुलिस के अनुसार , 10 जुलाई को संत तुकडोजी वाई निवासी इंद्रजीत हरिनारायन साहू (47) ने हिंगनघाट थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में उन्होंने बताया कि उनके घर के सामने खड़े ट्रैक्टर की बैटरी अज्ञात चोर ने चोरी कर ली. इसी तरह उस ट्रैक्टर के जगदीश कांबले और सतीश वरटकर के ट्रैक्टरों की बैटरियां भी चोरी हो गई थीं. हिंगनघाट पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की. पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर अपराध शाखा की टीम ने



जांच शुरू की गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने अंकिंत मोगरे, निवासी स्सीपर कॉलोनी को हिरासत में लिया. पुछताछ के दौरान आरोपी ने ट्रैक्टर बैटरियां चोरी करने की बात स्वीकार कर ली. आरोपी के घर से विभिन्न कंपनियों की तीन ट्रैक्टर बैटरियां, जिनकी अनुमानित कीमत 21 हजार रुपये है, तथा एक बिना नंबर की होडा एक्टिवा, जिसकी कीमत 50 हजार रुपये आंकी गई है, बरामद कर जप्त की गई.

संवाददाता । गड़चिरोली कोरोना महामारी की कालावधि में जिले की आंगनवाड़ी कर्मी और आशा वर्कर अपनी जान की परवाह न करते हुए सरकार द्वारा दिये गये निर्देश और सूचनाओं का पालन कर सेवा में जुट गयी थी. वहीं सरकार द्वारा संबंधित कर्मियों को कोरोना भत्ता के रूप में प्रति माह 1 हजार रुपये देने की घोषणा भी की गई. लेकिन संबंधित कर्मचारियों को करीब 24 माह का कोरोना भत्ता नहीं मिला है. इस बीच कर्मचारियों ने सरकार और प्रशासन को झापन सौंपकर बकाया कोरोना भत्ता देने की मांग की. लेकिन सरकार द्वारा कर्मियों की मांग की ओर अनदेखी



किये जाने के कारण कर्मचारियों ने आक्रमक रवैया अपनाते हुए अनेक बार आंदोलन भी किया. लेकिन अब 5 वर्षों की कालावधि बित जाने के बाद भी कर्मचारियों को बकाया भत्ता नहीं मिला है.

जिससे सोमवार को आंगनवाड़ी कर्मी और आशा वर्कर ने जिला परिषद पर मोर्चा निकालकर बकाया कोरोना भत्ता देने की मांग की है. इस आंदोलन का नेतृत्व में रमेशचंद्र दहिवडे, अमोल

नकली बीजों ने बढ़ाई चिंता

जिले में 305 से अधिक शिकायतें प्राप्त, दोषी कंपनियों पर कार्रवाई की मांग

संवाददाता । वर्धा खरीफ सीजन में समय पर बुआई के बाद अच्छी फसल की उम्मीद लगाए बैठे वर्धा जिले के किसानों की चिंता अब नकली और खराब गुणवत्ता वाले बीजों ने बढ़ा दी है. जिले के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें किसानों का आरोप है कि ब्रांडेड कंपनियों के सोयाबीन बीज बोने के बावजूद अंकुरण नहीं हुआ इससे किसानों के सामने दोबारा बुआई का संकट खड़ा हो गया है, जबकि बारिश की बेरुखी पहले से ही उनकी मुश्किलें बढ़ा रही है. जिले में खरीफ मौसम के लिए 418 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. कृषि विभाग के अनुसार अब तक 381 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई पूरी हो चुकी है. लेकिन पर्याप्त वर्षा नहीं होने और कई स्थानों पर बीजों के अंकुरित नहीं होने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाने की आशंका है. स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कृषि विभाग को अब



शिकायतों में इन नामचिन कंपनियों का समावेश

किसानों ने कुल 305 शिकायतें अब तक दर्ज की हैं. इसमें सर्वाधिक बूस्टर कंपनी से जुड़ी 186 शिकायतें हैं. इसके अलावा महाबीज की 21, इनोव्हेज की 15, यशोदा की 25, रवी सोइंस की 13 सहित अन्य बीज कंपनियों से जुड़ी शिकायतें भी हैं. फिलहाल अब तक कृषि विभाग ने 156 शिकायतों के संदर्भ में सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया है. अब कृषि विभाग क्या एक्शन लेता है, इस ओर सभी की निगाहें लगी है.

तक 305 से अधिक शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं. इनमें सबसे अधिक 181 शिकायतें देवली तहसील से मिली हैं. इसके अलावा आर्वी और आष्टी तहसीलों से भी बड़ी संख्या में किसानों ने बीजों के अंकुरन नहीं होने की शिकायत दर्ज कराई है. इसमें नामचिन कंपनियों के बीज हैं. शिकायतों के

बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए कृषि विभाग ने सक्रियता दिखाई है. विभागीय अधिकारी किसानों के खेतों का दौरा कर फसलों और बीजों की स्थिति का निरीक्षण कर रहे हैं साथ ही शिकायतों की जांच कर संबंधित कंपनियों से भी जवाब मांगा जा रहा है.

पालकमंत्री भोयर ने दिधे का किया सत्कार



संवाददाता । हिंगनघाट पालकमंत्री डा. पंकज भोयर ने भाजपा के जेष्ठ नेता किशोर दिधे का विशेष सत्कार किया. दिधे ने आज तक किए राजनितीक तथा सामाजिक कार्य का गौरव हो, यह इस सम्मान समारोह के पिछे का मुख्य उद्देश था. इस अवसर पर किशोर दिधे की पत्नी डा. किर्ती दिधे की उपस्थिति थी. कार्यक्रम में विधायक समीर कुणावार तथा नगराध्यक्ष डा. नयना तुलसकर प्रमुख रूप से उपस्थित थे. सत्कार समारोह में संबोधित करते हुए पालकमंत्री डा. पंकज भोयर ने कहा कि, दिधे ने केवल पार्टी संगठन को मजबूत बनाने जोर नहीं दिया, बल्कि राजनिती में अनेक युवा कार्यकर्ताओं को सही दिशा दिखाते हुए उन्हें

सक्षम नेतृत्व के रूप में निर्माण किया है. उनका यह मार्गदर्शन तथा सामाजिक कार्य के लिए दिया योगदान नई पीढ़ी के लिए निश्चित ही प्रेरणादायी है. इस समारोह में नगर परिषद उपाध्यक्ष निलेश ठोंबरे, निर्माणकार्य सभापति चंद्रकांत मालवे, डा. उमेश तुलसकर, भाजपा के संजय डेहणे, अंकुश ठाकुर, सेवानिवृत्त अभियंता किशोर डांगे, अनिल बंसोड, सामाजिक क्षेत्र के अभय मेंडमवार, अशोक चंदनखेडे, यशवंत शिंदे, किरण सायंकार, रोटरी अध्यक्ष संदीप डेहणे, संजय चांभारे, अरविंद डुंगरवाल, गोपाल वंगल, बालू इंगोले, रवी दांडेकर, विजय क्षीरसागर समेत पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे.

बड़ा हादसा टला, नई स्कूल भवन की हो रही मांग



संवाददाता / आर्वी वर्धा जिले के आर्वी तहसील अंतर्गत ग्राम धनोडी (नांदपुर) स्थित जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय की कक्षा का स्लैब गिरने से बड़ा हादसा टल

गया. यह घटना 11 जुलाई 2026 की रात को हुई. रात का समय होने और विद्यालय बंद रहने के कारन कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस घटना ने सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतों की

अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग

अरविंद लिल्लोरे ने ज्ञापन में कहा है कि यदि यह हादसा विद्यालय के समय हुआ होता तो गंभीर जनहानि हो सकती थी. इसलिए लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और विद्यालय के लिए तत्काल नया भवन स्वीकृत किया जाए. बताया गया है कि विद्यालय में केवल एक ही कक्ष है, जिसमें कक्षा पहली से पांचवीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है. विद्यालय में दो शिक्षिकाएं कार्यरत हैं. भवन की असुरक्षित स्थिति और पर्याप्त कक्षों के अभाव के कारण विद्यार्थियों की संख्या घटकर 24 रह गई है.

स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस मामले को लेकर ग्राम नांदपुर निवासी अरविंद लिल्लोरे ने 13 जुलाई को उपविभागीय अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस को ज्ञापन सौंपकर जिला परिषद वर्धा और पंचायत समिति आर्वी के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. ज्ञापन में कहा गया है कि

विद्यालय भवन की जर्जर स्थिति के बारे में करीब एक वर्ष पहले ही विद्यालय की मुख्याध्यपिका रेखा हिवाले तथा ग्राम को उपविभागीय अधिकारी के सरपंच कोमल धनोडी (नांदपुर) की सरपंच समिति, आर्वी और जिला परिषद, वर्धा को लिखित रूप से अवगत कराया था. साथ ही पुराने भवन को ध्वस्त कर नया भवन बनाने का अनुरोध भी किया गया

था. इसके बावजूद संबंधित अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया. ज्ञापन में मुख्यमंत्री से ग्रामीन क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों को सुरक्षित और आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाने तथा धनोडी (नांदपुर) प्राथमिक विद्यालय के नए भवन के निर्माण के लिए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की गई है.

तिरोड़ा में मिशन वात्सल्य समिति की बैठक संपन्न

एकल महिलाओं को शासकीय योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने पर जोर , विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा

संवाददाता / तिरोड़ा
महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त के मार्गदर्शन में मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत तालुका स्तरीय समिति की बैठक 7 जुलाई 2026 को तहसीलदार एवं समिति के अध्यक्ष नारायण ठाकरे की अध्यक्षता में तिरोड़ा तहसील कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में एकल महिलाओं के कल्याण और उन्हें विभिन्न शासकीय योजनाओं का प्रभावी लाभ उपलब्ध कराने को लेकर

विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में समिति के सदस्य ज्योति भालाधरे, नागेश लोणारे, विनायक दडसपाटील, रुद्रसेन रहांगडाले, एल. जी. निपाने, कणकलता काळे, पुष्पा भांडारकर, सोनाली बोबडे, दीपाली नवथडे, शकुंतला दानवे, शीला अंबुले, प्रदीप मेश्राम, रत्नाकर नंदागवडी, संगीता पंचबुधे तथा टेकचंद चौधरी उपस्थित रहे। समिति के सचिव एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी



विनोदकुमार चौधरी ने बैठक का वात्सल्य के अंतर्गत तालुका की एकल महिलाओं को विभिन्न शासकीय

योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से संबंधित विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत की तथा लाभार्थियों तक योजनाओं की पहुंच बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जानकारी दी गई कि बाल संगोपन योजना के अंतर्गत अब तक 52 महिलाओं

को लाभ स्वीकृत किया जा चुका है। बैठक में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि पात्र महिलाओं तक सभी योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचे। तहसीलदार एवं समिति के अध्यक्ष नारायण ठाकरे ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे एकल महिलाओं को अधिकाधिक योजनाओं से जोड़ने के लिए समन्वित प्रयास करें तथा लाभार्थियों की अद्यतन जानकारी नियमित रूप से समिति के सचिव को उपलब्ध कराएं, ताकि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की सतत समीक्षा की जा सके। बैठक के अंत में स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ) के प्रतिनिधि प्रदीप मेश्राम ने अध्यक्ष, समिति के सदस्यों एवं उपस्थित अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। बैठक सकारात्मक वातावरण में संपन्न हुई, जिसमें एकल महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

भीवरामजी विद्यालय एवं कनिष्ठ महाविद्यालय वडेगांव में वृक्षारोपण अभियान

विद्यार्थियों ने लिया पर्यावरण संरक्षण का संकल्प

संवाददाता / तिरोड़ा
पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देने और विद्यार्थियों में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के उद्देश्य से हरित सेना एवं इको क्लब के संयुक्त तत्वावधान में भीवरामजी विद्यालय एवं कनिष्ठ महाविद्यालय, वडेगांव में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय परिसर में आयोजित इस अभियान में प्राचार्य डी. आर. गिरीपुंजे तथा हरित सेना एवं इको क्लब प्रभारी शिक्षिका नंदा बोरकर की प्रमुख उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों और शिक्षकों ने मिलकर विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम की शुरुआत



प्राचार्य डी. आर. गिरीपुंजे द्वारा लाए गए बादाम सहित अन्य छायादार एवं उपयोगी वृक्षों के पौधों के रोपण से हुई। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाना और उनकी नियमित देखभाल करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वृक्ष केवल

पर्यावरण को संतुलित नहीं रखते, बल्कि मानव जीवन, जैव विविधता और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए भी अनिवार्य हैं। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाकर उसका संरक्षण करने का संकल्प लेना चाहिए।

हरित सेना एवं इको क्लब प्रभारी शिक्षिका नंदा बोरकर ने भी विद्यार्थियों को वृक्षों के महत्व से

अवगत कराया। उन्होंने बताया कि विद्यालय स्तर पर समय-समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि विद्यार्थियों में प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित हो और वे पर्यावरण संरक्षण के सक्रिय भागीदार बन सकें। वृक्षारोपण अभियान में विद्यालय के छात्र सुचित राणे, हर्ष कोटांगले, ऋषभ कुडे, द्रूप बोपचे, लक्ष्य गौतम, सोहम माहुरकर, आर्यन राऊत, आदर्श बोपचे, दिव्यांशु बडगे, सक्षम चौरे, विहान बोपचे, दक्ष वाघमारे, खुमांशु रहांगडले तथा चिराग पारधी ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई। सभी विद्यार्थियों ने लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल करने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों ने भी महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया।

जि.प. शाला में ‘न्यू कॉन्वेंट’ शुरु



गोंदिया : हलबीटोला के जि.प. विरिष्ठ प्राथमिक स्कूल में ‘न्यू कॉन्वेंट’ कक्षा का शुभारंभ किया गया. इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को अंग्रेजी के साथ-साथ मातृभाषा में भी गुणवत्तापूर्ण व आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराना है. कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला परिषद सदस्य ममता बाढवे ने की, उद्घाटन पं. स. सभापति मुनेश रहांगडाले ने किया. मुख्य मार्गदर्शक के रूप में डायट प्राचार्य राजकुमार हिवारे उपस्थित थे. इस अवसर पर प्रा.पं. सदस्य सरस्वता मेश्राम, केंद्र

प्रमुख लीना पटले, शालेय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष संजय तुरकर तथा वशिष्ठ खोब्रागड़े मौजूद थे. कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन व सावित्रीबाई फुले एवं मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुआ. इसके पश्चात रहांगडाले ने कीर्ता काटकर कक्षा का विधिवत उद्घाटन किया. नवप्रवेशित बच्चों का तिलक लगाकर तथा उनके पालकों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया. सभापति ने विद्यालय की भौतिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया.

तीन महीने से वेतन के इंतजार में ग्राप कर्मचारी

संवाददाता / गोंदिया
देवरी पंचायत समिति अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में कार्यरत कर्मचारियों को मार्च 2026 का वेतन और भविष्य निधि (पीएफ) पिछले तीन महीनों से नहीं मिला है. समय पर वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट गहरा गया है और उनके परिवारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है. ग्राम पंचायत कर्मचारी तहसील संगठन के अनुसार, मार्च 2026 के वेतन के लिए आवश्यक राशि गोंदिया जिला परिषद द्वारा लगभग तीन माह पहले ही देवरी पंचायत समिति को उपलब्ध करा दी गई थी. इसके बावजूद पंचायत समिति प्रशासन की कथित लापरवाही और देरी के कारण आज तक कर्मचारियों के बैंक खातों में वेतन और पीएफ की राशि



जमा नहीं की गई है. संगठन का आरोप है कि कर्मचारी कई बार संबंधित अधिकारियों से वेतन जारी करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें केवल 'आज होगा, कल होगा' जैसे आश्वासन ही दिए जा रहे हैं. इससे कर्मचारियों में भारी नाराजगी और असंतोष का माहौल है. मार्च महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों को बैंक कर्जों की किस्तें चुकाने, बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने, घर का खर्च चलाने, इलाज कराने और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. कई कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो गई है और मानसिक तनाव बढ़ रहा है. ग्राम पंचायत कर्मचारी तहसील संगठन ने प्रशासन से लंबित वेतन और पीएफ की राशि तत्काल कर्मचारियों के खातों में जमा करने की मांग की है. संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र भुगतान नहीं किया गया तो पंचायत समिति प्रशासन के खिलाफ तीव्र आंदोलन शुरू किया जाएगा.

स्मार्ट मीटरमध्ये कॅमेरा असल्याचा खोटा आरोप

ग्राहक प्रतिनिधीसह यूट्यूब संपादकाविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल कपोलकल्पित माहितीवर विश्वास ठेवू नका - महावितरणचे आवाहन

संवाददाता / गोंदिया
महावितरणच्या स्मार्ट मीटरमध्ये ‘कॅमेरा’ असल्याचा खोटा आरोप करून आणि सोशल मीडियाद्वारे त्याचा हेतुपुरस्सर प्रसार करीत नागरिकांमध्ये भीती व दहशतीचे वातावरण निर्माण करणारे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्राहक संघटनेचे नंदन मेघश्याम वेगुलेंकर व ‘कोकणसाद’ यूट्यूब न्यूज चॅनेलचे संपादक सागर चव्हाण यांच्याविरुद्ध सावंतवाडी (जि. सिंधुदुर्ग) पोलीस ठाण्यात रविवारी (दि. 12) फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले. या खोट्या आरोप प्रकरणी महावितरणकडून गंभीर दखल घेण्यात आली. स्मार्ट मीटरबाबत कपोलकल्पित तसेच नागरिकांमध्ये भीती व दहशत निर्माण होईल असे जाहीर व रेकॉर्डेड वक्तव्य केल्याप्रकरणी नंदन वेगुलेंकर आणि केवळ सनसनाटी निर्माण करण्यासाठी ही खोटी माहिती सर्व सोशल मीडियाच्या खात्यांवरून प्रसारित केल्याप्रकरणी यूट्यूबचे संपादक सागर चव्हाण यांच्याविरुद्ध जनतेत भीती निर्माण करून गुन्हास विधावणी देणे, गुन्हेगारी पद्धतीने धमकावणे, शांततेचा भंग करण्यासाठी जाणीवपूर्वक अपमान करणे, बदनामी करणेबाबत सावंतवाडी पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय सहितेनुसार कलम 353 (1) (बी), 351 (3), 352 व 356 अन्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले. याप्रकरणी सावंतवाडी पोलीस

पुढील तपास करीत आहे. स्मार्ट मीटर हे पूर्णपणे सुरक्षित आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित आहेत. त्यात कोणताही ‘कॅमेरा’ किंवा गोपनीयतेचा भंग करणारी यंत्रणा नाही. वीजग्राहकांनी स्मार्ट मीटरबाबत पूर्णतः निश्चित राहावे. कोणत्याही कपोलकल्पित माहिती व खोटरड्या आरोपांना बळी पडू नये असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे. स्मार्ट मीटरबाबत अत्यंत खोटी व काल्पनिक माहिती पसरवणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी तक्रार दाखल करण्यात येत असल्याचे देखील महावितरणतर्फे स्पष्ट करण्यात आले. याबाबत माहिती अशी की, सावंतवाडी (जि. सिंधुदुर्ग) येथे कोकणसाद यूट्यूब न्यूज चॅनेलमध्ये स्मार्ट मीटर संदर्भात चर्चासत्र ठेवण्यात आले. त्यांचे रेकॉर्डिंग शुक्रवारी (दि. 10) सायंकाळी करण्यात आले. या चर्चासत्रामध्ये महावितरणकडून उपकार्यकारी अभियंता योगेंद्र वाघ, ग्राहक संघटनेचे नंदन वेगुलेंकर तसेच दीपक पटेकर सहभागी झाले होते. यामध्ये महावितरणकडून स्मार्ट मीटरबाबत विविध फायद्यांची माहिती देण्यात आली तसेच विविध आरोपांचे सर्मपक खुलासे करण्यात आले. तथापि, या चर्चासत्रामध्ये नंदन वेगुलेंकर यांनी स्मार्ट मीटरमध्ये ‘कॅमेरा’ असल्याचा धादांत खोटा आरोप केला. स्मार्ट मीटरमुळे

नागरिकांच्या खाजगी आयुष्यावर पाळत ठेवली जात असल्याचा अत्यंत हास्यास्पद दावा त्यांनी व्हिडिओच्या माध्यमातून केला. याबाबत महावितरणचे री. वाघ यांनी त्याचवेळी स्पष्टीकरण दिले. तरीसुद्धा कोकणसाद यूट्यूब न्यूज चॅनेलने त्यांच्या इतर सोशल मीडियाच्या खात्यांवरून स्मार्ट मीटरमध्ये ‘कॅमेरा’ असल्याची खोटी जाहिरात केली आणि या चर्चासत्रातील संदर्भ वागळून दिशाभूल करणारा 2 ते 3 मिनिटांचा भाग ‘स्मार्ट मीटरची चिरफाड’ या मथळ्याखाली रिलच्या माध्यमातून हेतुपुरस्सरपणे प्रसारित केला. त्यात महावितरणकडून करण्यात आलेला खुलासा देखील वागळण्यात आला.

नाम बदल सुचना

मै अनमोल क्रांतीकुमार जैस्वाल घोषित करता हूँ। कि मेरा पहले नाम अनमोल क्रांती जैस्वाल था। मेरा पुरा नाम अनमोल क्रांतीकुमार जैस्वाल है। वास्ते मुझे आज से अनमोल क्रांतीकुमार जैस्वाल के नाम से जाना जाए।

अनमोल क्रांतीकुमार जैस्वाल
मोदी पेट्रोल पंप के पीछे
बजाज वाई गोंदिया
मो. ९८३४२७२६०६

QUOTATION NOTICE No.38/2026-27
Inviting Rates for the following Items

The Quotations are invited by Executive Engineer, P.W.Dn. (Electrical), Civil Lines Nagpur for Estimate purpose from Dealer/Supplier/Contractor for the following materials should be downloaded from Government website www.mahapwd.gov.in "pay pwd online", shall be submitted to the Office of the Executive Engineer, P. W.Dn. (Electrical), Civil Lines Nagpur in sealed envelope as below mentioned Date.

Name Of Work: Providing E.I, EPABx System, LAN & Networking, CCTV System, Area Lighting, Submersible Pumps, Fire Fighting System. On Grid Solar System, DG Set, Electric Vehicle Charging System, & Transformer to Newly Constructed Tahsil Building at Arjuni Morgoan, Tah-Arjuni Morgoan, Dist-Gondia.

S.N.	Description Of Item	Qty	Unit	Rate
1	Supplying, erecting, testing and commissioning of diesel generating set with alternator of 82.5 KVA confirming to CPCB-IV plus Emission Compliant with output continuous rating, 3 Phase, 415V, 50c/s 0.8 p.f.A.C supply, a totally enclosed liquid cooled multi in line cylinder diesel engine developing suitable BHP at 1500 rpm with 10% overload for 1 hour in 12 hours, along with standard accessories, self-excited, self-regulated, screen protected alternator with static excitation system running at 1500 RPM as per IS 4722-2001 with voltage regulation +/-0.5%, with performance class G2 Both the engine and alternator direct coupled on a common fabricated steel base frame and mounted on anti-vibrating pads with standard control panel comprising meters, switchgears, indicators connected with suitable wires/cables, the complete set enclosed in composite Acoustic enclosure as fully assembled integral unit made of 16 SWG CRCA Sheet, sound absorbing material to restrict sound level up to 75 dB at 1.0 m, with suitable capacity DEF tank provided with first filling of oil, diesel tank capacity not less than 145 Litres etc. on provided M20 Grade CC Foundation and obtaining necessary approval from Electrical Inspector if necessary. This D.G set is Fitted in Soundproof & Weather Proof Acoustic Enclosure as per CPCB IV plus Emission Compliant (with acoustic enclosure as per latest Government norms) approved Norms.	1.0	Each	

Note: Rates shall be without GST
Quotation available from: Dt. 14/07/2026 To 20/07/2026
Date of Submission:- Dt. 21/07/2026
No. EEN/1800 /2026-27
Office of Executive Engineer
P.W.D. Electrical Division, Nagpur
Date: 09/07/2026

Executive Engineer
Nagpur Electrical Division Nagpur

क्र. संभावज/नाम/ २२४/ २० २६